बजट विकसित भारत का रोडमैप : पीएम

'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' विषय पर वेबिनार

नई दिल्ली, 27 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त' विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पॉलिसी रोडमैप होता है.

उन्होंने कहा कि बजट का मूल्यांकन उन नीतियों से होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, क्रेडिट फ्लो आसान बनाएं.ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, गवर्नेंस में पारदर्शिता लाएं और नागरिकों का जीवन सरल बनाएं.

वेबिनार को प्रभावी ब्रेन स्टॉर्मिंग बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के बाद होने वाले वेबिनार केवल विचार-विमर्श तक सीमित न रहें, बल्कि व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित प्रभावी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मंच बनें. उन्होंने उद्योग, शिक्षाविदों, विश्लेषकों और नीति-निर्माताओं की संयुक्त भागीदारी को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सटीक परिणामों के लिए आवश्यक बताया.

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से दीर्घकालिक उत्पादकता

पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष फोकस रखा गया है. हाईवे, रेलवे, पोर्ट, डिजिटल नेटवर्क और पावर सिस्टम जैसे ठोस परिसंपत्तियों से दीर्घकालिक उत्पादकता पैदा होगी. उन्होंने बताया कि 11 साल पहले सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. यह निवेश निजी क्षेत्र के लिए भी स्पष्ट संकेत है.

मोदी-शाह पर प्राथमिकी दर्ज करने वाले वकील को फटकार

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले एक वकील की फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान चेतावनी दी कि किसी कानून या विचारधारा से असहमति को आपराधिक अपराध में नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने पूछा, अगर संसद कोई अवैध कानून पारित करती है, तो क्या यह अपराध है? अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका समाधान संवैधानिक चुनौती में है.

अमेरिकी अदालतों से भारतीयों को राहत

वॉशिंगटन, 27 फरवरी. अमेरिका की विभिन्न जिला अदालतों ने इमिग्रेशन डिटेंशन में रखे गए कई भारतीय नागरिकों को इस सप्ताह राहत दी है.

कैलिफोर्निया, मिशिगन, न्यूयॉर्क और ओक्लाहोमा की अदालतों ने बॉन्ड सुनवाई कराने या तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए. अदालतों ने माना कि कई मामलों में गलत डिटेंशन कानून लागू किया गया या पर्याप्त विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ.

कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में हरबीत सिंह को सात दिनों के भीतर व्यक्तिगत बॉन्ड सुनवाई का आदेश दिया गया. मिशिगन में सागर राम को पांच कार्यदिवस में सुनवाई या रिहाई का निर्देश मिला.

ओक्लाहोमा में करनदीप सिंह के मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी हिरासत बॉन्ड योग्य प्रावधान के तहत आती है. न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन अदालत ने हरमनप्रीत सिंह को हैबियस राहत देते हुए नई बॉन्ड सुनवाई का आदेश दिया. भवानदीप सिंह ढालीवाल और विक्रांत सिंह की तत्काल रिहाई भी निर्देशित की गई. हालांकि, मिशिगन में गुरप्रीत वालिया सिंह की याचिका खारिज कर दी गई. कुछ अन्य मामलों में भी अदालत ने राहत देने से इनकार किया.

एक करोड़ 23 लाख रुपए का 246 किलोग्राम गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार

किशनगंज, 27 फरवरी. बिहार में किशनगंज जिले की पुलिस ने 246 किलोग्राम गांजा बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को सूचना मिली थी कि असम से गलगलिया के रास्ते ट्रक में छिपा कर अवैध मादक पदार्थ बिहार लाया जा रहा है जो अररिया की ओर जाएगा.

इस सूचना के आधार पर ठाकुरगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) 2 मंगलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. इसके बाद बंगाल की ओर से आने वाली सभी वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही थी. सूत्रों ने बताया कि वाहन चेकिंग के क्रम में एक असम नंबर ट्रक को रोका गया ,जिसमें उपर से सीमेंट लदा हुआ दिखाई दिया. चालक से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गयी.

तलाशी के दौरान सीमेंट के नीचे ट्रक में विशेष रूप से बनाये गये तहखाने में छुपाकर रखा गया 246 किलो गांजा बरामद किया गया.बरामद गांजा की कीमत एक करोड़ 23 लाख रूपये है.इस दौरान चालक मोहम्मद इम्तियाज और सह चालक विजय कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है.

मुख्तार के शूटर शोएब की दिनदहाड़े हत्या

बाराबंकी. बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह 50 साल का था. वारदात शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे हुई, जब वह कार से लखनऊ से बाराबंकी जा रहा था. हाईवे से 100 मीटर आगे बढ़ते ही दो बाइक सवार बदमाश आ गए. जब तक शोएब कुछ समझ पाता, उसकी कार पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शोएब पर 15 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं. वारदात के बाद हमलावर अयोध्या की तरफ फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पहुंची और शोएब को अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

तमिलनाडु : 188 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित

▸ बनेंगे 75 हजार पोलिंग बूथ : सीईसी

चेन्नई, 27 फरवरी. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आयोग पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में है और जिला कलेक्टरों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहा है.

इसी दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि वर्तमान में तमिलनाडु में 5 करोड़ 67 लाख मतदाता हैं.

राज्य में 2.89 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि 2.77 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं. वहीं, पूरे राज्य में 7,617 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं. 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 4 लाख है और 100 साल से ज्यादा उम्र के 2,530 वोटर्स हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नामों को मतदाता सूची से सही तरीके से हटाया गया है. उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो. सीईसी ने बताया कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 188 सामान्य, 44 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. इस बार पूरे राज्य में लगभग 75,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से लगभग 44,000 ग्रामीण इलाकों में होंगे. सीईसी ने आगे बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर मतदान केंद्र पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी.

पीएमएलए मामले में ईडी ने 90 करोड़ की संपत्ति की जब्त

▸ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू

नई दिल्ली, 27 फरवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और मुख्य नियंत्रक इंदरजीत सिंह यादव और अन्य से जुड़े एक मामले में 90.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है.

ईडी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में इंदरजीत सिंह यादव और उसकी पत्नी रीना कुमारी के मालिकाना हक वाले कई प्लॉट/जमीन और आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्ति भी शामिल हैं. ईडी ने इंदरजीत सिंह यादव और उनके साथियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक प्राथमिकी और दाखिल किए गए आरोप-पत्र के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की है.

प्राथमिकी के मुताबिक जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेम्स ट्यून्स के नाम से काम करने वाली) का मालिक और मुख्य नियंत्रक इंद्रजीत सिंह यादव एक दबंग व्यक्ति हैं, जो हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं से दिए गए कर्ज की जबरदस्ती वसूली, धोखाधड़ी, गैर-कानूनी जमीन हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं.

होली से पहले वेतन, तीन दिन अवकाश : योगी

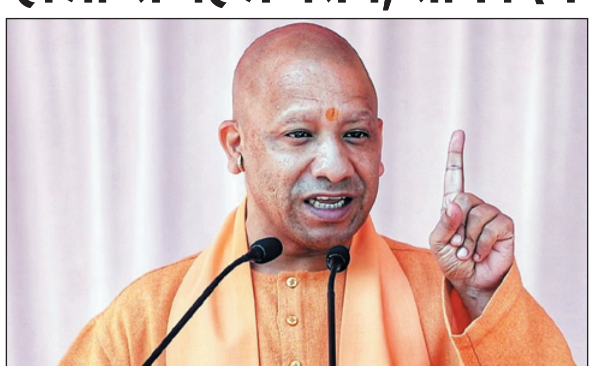

लखनऊ,27 फरवरी. उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा और सफाई कर्मचारियों समेत सभी सरकारी कर्मियों को होली से पहले वेतन देने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन मिल जाएगा, जिससे वे होली की तैयारियां सुचारु रूप से कर सकें.राज्य में शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया गया है.

जबकि 2 मार्च से 4 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. इस प्रकार कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा. उधर, कृषि विभाग ने भी किसानों के लिए होली पर विशेष पहल की है. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है, जो 4 मार्च तक चलेगी. किसान विभागीय वेबसाइट पर 'किसान कॉर्नर' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. चयनित लाभार्थियों को टोकन कन्फर्म होने के 10 दिन के भीतर यंत्र खरीदकर रसीद और फोटो वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी.

फर्जी शेयर ट्रेडिंग घोटाले में युवक से 94 लाख से अधिक की ठगी

नासिक, 27 फरवरी. महाराष्ट्र में नासिक के एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों ने 94 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है जिसके बाद क्राइम पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता निलेश भाडके के अनुसार, उन्हें 15 अक्टूबर को एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें शेयर बाजार में निवेश कर भारी लाभ कमाने का दावा किया गया था. संदेश पर भरोसा कर उन्होंने प्रेषक से संपर्क किया, जिसके बाद उन्हें एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ दिया गया. ग्रुप में खुद को बाजार विशेषज्ञ बताने वाले लोग निवेश संबंधी टिप्स और बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा कर रहे थे, जिससे पूरे सेटअप को वैध और भरोसेमंद दिखाया गया. अगले ही दिन श्री भाडके से एक ऑनलाइन निवेश फॉर्म भरवाया गया और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा गया. ऐप पर खाता खोलने के बाद उन्होंने शुरुआत में छोटी राशि निवेश की. प्लेटफॉर्म पर दिख रहे आकर्षक रिटर्न से प्रभावित होकर उन्होंने धीरे-धीरे निवेश बढ़ा दिया. इस दौरान उन्होंने 10 किश्तों में कुल 94,47,744 रुपये ट्रांसफर किए. ऐप में उनकी राशि करोड़ों रुपये में बढ़ती हुई दिखाई गई. जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने 'टैक्स' के नाम पर अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग की.

परमाणु मुद्दे पर अमेरिका-ईरान के बातचीत खत्म

जिनेवा, 27 फरवरी. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियारों के मुद्दे पर तीसरे दौर की बातचीत यहां समाप्त हो गयी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देश अगले हफ्ते वियना में तकनीकी स्तर की बातचीत कर सकते हैं.

अमेरिका इस बात को लेकर सोच रहा है कि क्या नयी कूटनीति से ईरान के परमाणु हथियारों के इरादों पर रोक लग सकती है या आखिरकार सैन्य बलों का ही सहारा लेना पड़ सकता है. बातचीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर फोर्डो, नतांज़ और इस्फ़ाहान में अपने परमाणु केंद्रों को खत्म करने और यूरेनियम के बचे हुए भंडार को देश से बाहर भेजने का दबाव डाला है.

अमेरिका ने कर्मचारियों की रवानगी को दी मंजूरी

यरूशलम. इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं के कारण गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को इजराइल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है. दूतावास ने एक वक्तव्य में कहा कि जब तक व्यावसायिक उड़ानों का संचालन हो रहा है, तब तक व्यक्तियों को इजराइल से बाहर जाने पर विचार कर लेना चाहिए. वक्तव्य में कहा गया है, 'सुरक्षा घटनाओं के जवाब में और बिना किसी अग्रिम सूचना के', अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

एक नजर में

जेएनयू प्रदर्शन मामले में 14 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 फरवरी. राष्ट्रीय राजधानी में गुरूवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद 14 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी .गिरफ्तार किए गए लोगों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार और संयुक्त सचिव दानिश अली आदि शामिल हैं. वसंत कुंज उत्तर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये गिरफ्तारियां जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों द्वारा परिसर के साबरमती टी पॉइंट से शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करने की कोशिश के बाद हुईं. यह विरोध प्रदर्शन कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित द्वारा एक पॉडकास्ट पर यूजीसी के नियमों को लागू करने, पदाधिकारियों को निकालने और प्रस्तावित रोहित एक्ट के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ा था .पुलिस ने मार्च को विश्वविद्यालय गेट के पास बैरिकेड्स पर रोक दिया, जिसके बाद थोड़ी झड़प हुई. पुलिस ने आरोप लगाया कि टकराव के दौरान कुछ छात्रों ने मारपीट की और कई लोग घायल हो गए .एक बयान में छात्र यूनियन ने बहुत ज़्यादा पुलिस बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया और दावा किया कि इस घटना के दौरान कई छात्र घायल हुए और बी आर अंबेडकर की एक तस्वीर

चीन ने पाक-अफगान से युद्धविराम की अपील की

बीजिंग, 27 फरवरी. चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंसक झड़पों को लेकर बहुत चिंतित है और उसने दोनों पक्षों से युद्धविराम के लिए बातचीत की है. गौरतलब है कि इन झड़पों में 133 अफगान तालिबान लड़ाके और पाकिस्तान के दो जवान मारे गये हैं .विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर बमबारी के बाद चीन संघर्ष के बढ़ने पर बहुत चिंतित है. चीन ने दोनों पक्षों से शांत रहने और संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके युद्धविराम और खून-खराबा से बचा जाना चाहिए .उन्होंने कहा, 'चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष में लगातार मध्यस्थता की है और आगे भी तनाव कम करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखने को वह तैयार है.' उन्होंने कहा कि मंत्रालय और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में चीन के दूतावास इस मामले पर दोनों देशों में संबंधित पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं. इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए.

वेनेजुएला ने 19 तेल समझौतों को किया निलंबित

काराकार, 27 फरवरी. वेनेजुएला के तेल मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ किए गए 19 तेल और गैस प्रोडक्शन-शेयरिंग समझौतों को निलंबित कर दिया है. यह समझौते पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में हुए थे. इन अनुबंधों की वैधता और कंपनियों के बैकग्राउंड की समीक्षा की जा रही है. इन समझौतों को सस्पेंड करने से देश के तेल और गैस उत्पादन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है. वेनेजुएला और अमेरिका इन एग्रीमेंट्स की शर्तों की समीक्षा कर रहे हैं. कुछ मामलों में उन्हें रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है. हाल ही में हाइड्रोकार्बन कानून में संशोधन के बाद सरकार को मौजूदा एग्रीमेंट्स की समीक्षा के लिए छह महीने का समय मिला है.

बरसाना में पारंपरिक लट्ठ मार होली में दिखा उत्साह

▸ हुरियारों-हुरियारिनों ने लिया राधा-कृष्ण स्वरूप

मथुरा , 27 फरवरी. होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन ब्रज में यह पर्व एक दिन का नहीं, बल्कि आस्था और परंपराओं से भरा एक भव्य उत्सव है, जो बसंत पंचमी से शुरू होकर लगभग 40 दिनों तक विभिन्न पारंपरिक तरीकों से मनाया जाता है.

ब्रज की उन्हीं पारंपरिक होली में से एक लट्ठमार होली को मथुरा के बरसाना में गुरुवार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर बरसाना की हुरियारिनों ने राधा रानी की सखियों का स्वरूप धारण कर फगुआ (उपहार) लेने के लिए नंदगांव में प्रवेश किया. वहीं, नंदगांव के हुरियारे ने बरसाना से आईं हुरियारिनों के साथ लट्ठमार होली खेली. परंपरा के अनुसार, जैसे ही बरसाना की हुरियारिनों ने नंदगांव में प्रवेश किया, पूरा क्षेत्र राधा-कृष्ण की रंगीली लीलाओं के रंग में सराबोर हो उठता है. चारों ओर भक्ति और प्रेम का रस फैल जाता है.नंदगांव के हुरियारे कृष्ण स्वरूप में उनका स्वागत करते हैं और इसके बाद नंदगांव के ऐतिहासिक नंद चौक व रंगीली चौक पर जमकर होली खेली जाती है.

ढोल, नगाड़ों और रसिया गायन के बीच गुलाल उड़ता है, लट्ठमार की प्रतीकात्मक छेड़छाड़ होती है और पूरा वातावरण 'राधे-राधे' व 'श्याम' के जयकारों से गूंज उठता है. यह अनोखी परंपरा ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है, जहां प्रेम, हास्य और भक्ति का संगम देखने को मिलता है.

देरी को माफ करने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज

▸ मामला 66 .35 लाख रुपये की मध्यस्थता देनदारी से जुड़ा

▸ आवेदन में 293 दिनों की देरी स्वीकार की गई

शिमला. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता मामले में अपील दायर करने में 300 से अधिक दिनों की देरी को माफ करने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इतनी लंबी देरी के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी.

अदालत ने बताया कि अपील 323 दिनों की देरी से दायर की गई, जबकि आवेदन में 293 दिनों की देरी स्वीकार की गई थी. पांच नवंबर 2024 के फैसले की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन भी लगभग दस महीने बाद 16 सितंबर 2025 को किया गया. पीठ ने इसे राज्य की 'घोर निष्क्रियता' करार दिया. सरकार ने तर्क दिया कि उसे निर्णय की जानकारी जुलाई 2025 में निष्पादन याचिका दायर होने के बाद मिली, लेकिन अदालत ने कहा कि मुकदमों की निगरानी विभाग की जिम्मेदारी है. मामला 66.35 लाख रुपये की मध्यस्थता देनदारी से जुड़ा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि देरी की माफी अपवाद है, नियम नहीं, और राज्य के विरुद्ध निर्णय प्रवर्तनीय रहेगा.

आज का इतिहास

1568- अकबर की सेना ने चार महीने की कड़ी घेराबंदी के बाद चितौड़गढ़ किला जीत लिया.

1922- मिस्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया.

1928- सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ.

1936- भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ.

1942- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने जावा द्वीप पर कब्जा किया, जो 1945 तक उनके अधीन रहा.

1948- भारत की स्वतंत्रता के छह महीने बाद, ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी अपने देश लौट गई.

सम्मेलन | **नेपाली सेना में भारतीय सेना के जनरल रहे अधिकारी ले रहे हिस्सा**

सेना प्रमुखों ने सुरक्षा चुनौतियों के प्रमुख मुद्दों पर की चर्चा

नयी दिल्ली 27 फरवरी. सेना प्रमुखों का दसवां सम्मेलन शुक्रवार को यहां शुरू हुआ जिसमें सेनाओं की संचालन तत्परता, क्षमता विकास और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गयी. दो दिन के इस सम्मेलन में सेना के पूर्व प्रमुखों के अलावा नेपाली सेना में भारतीय सेना के मानद जनरल रहे सैन्य अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.

नेपाल सेना के इन शीर्ष सैन्य अधिकारियों की भागीदारी सम्मेलन की विश्व स्तर पर अद्वितीय और ऐतिहासिक सैन्य परंपरा को दर्शाती है जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और एक समान सैन्य विरासत पर आधारित भारत-नेपाल के असाधारण और स्थायी सैन्य संबंधों का प्रतीक है. यह विशिष्ट व्यवस्था भारत के 'विश्वबंधु' के सभ्यतागत लोकाचार और 'पड़ोसी पहले' के सिद्धांत के अनुरूप है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सुदृढ़ और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

यह सम्मेलन मौजूदा सैन्य नेतृत्व और पूर्व सेना प्रमुखों के बीच पेशेवर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करता है, जो पीढ़ियों के बीच निरंतरता और सामूहिक ज्ञान को मजबूत करता है. कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुआ जिसके बाद संचालन विकास और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. पूर्व सेना प्रमुख निर्धारित कार्यक्रमों के चुनिंदा सैन्य प्रतिष्ठानों और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे.

इलाहाबाद कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

वाराणसी, 27 फरवरी. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद कहा कि उनके खिलाफ 'मीडिया ट्रायल' चलाया जा रहा था और कोर्ट के बाहर ही फैसला सुनाया जा रहा था.

उन्होंने कहा, 'न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हमने जो दलीलें रखीं कि मुकदमा झूठा बनाया गया है, माननीय न्यायाधीश ने उनमें बल पाया और इसी आधार पर आदेश पारित किया. न्यायालय ने हमारी बात को समझा है. बटुक आश्रम में रहने संबंधी जो व्यापक प्रचार किया गया, वह प्रमाणित नहीं हो सका. फर्जी कहानी बनाकर देश को भ्रमित किया गया.' शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से न्यायालय में किसी सीडी का उल्लेख तक नहीं किया गया, जबकि मीडिया में इस विषय को उछाला जा रहा था.

उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोर्ट के बाहर ही ट्रायल चलाया जा रहा था. उन्होंने संकेत दिया कि आगे मानहानि की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे. उन्होंने प्रश्न उठाया कि यदि न्यायालय ने आज प्रक्रिया संबंधी बातें स्पष्ट की हैं तो पूर्व में पुलिस स्तर पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई.